and distribute the surplus land among the landless persons; and

(c) what are the names of States which have taken steps in accordance with the guide lines issued by the Central Government in this regard and what are the reasons for noneompliance of the same by the remaining States ?]

कृषि ग्रीर सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रमुक्तल प्रदेल): (क) से (ग) कृषि जीतों की अधिकतम सीमा के संबन्ध में 1972 में हुए मुख्य मंज्ञियों के सम्मेलन की सिफारिशों के बाधार पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्भी सिद्धान्तों में यह विहित है कि अधिकतम जीत संबन्धी संशोधित कानून 24 जनवरी, 1971 से पहले की पिछली तारीख से लागू किए जाने चाहिए भीर ऐसे कानूनों में विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उस तारीख के बाद किए गए भूमि के किसी भी हस्तान्तरण का वास्तविक टहराने का दायित्व हस्तान्तरणकर्ता को होगा । इमकी मंगा अन्य बातों के साथ साथ जोत संबन्धी कानुनों के प्रभाव से वचने ग्रीर उन्हें टालने के प्रयोजन से किए जाने वाले बेनामी हस्तान्तरणीं को समाप्त करना या। सभी राज्यों के जोत की सीमा संबन्धी कानूनों को पिछली तारीखों से इस प्रकार लागू करने की व्यवस्था है जिससे जाली हस्तान्तरणों को ग्रस्वीकार किया जा सकता <u>₹</u> 1

t[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION **PRABHUDAS** (SHRI PATEL): (a) to (c) The national guidelines on agricultural land ceilings issued by the Government of India on the basis of the recommendations of the Chief Ministers' Conference of 1972 laid down that the amended ceiling laws should be given retrospective effect from a date not later than the 24th January, 1971, and that a specific provision should be made in the ceiling law making it clear that the onus of proving the bona fide nature of any transfer of land made after that

t[] English translation.

22 RSS/76-5

(b) if so, what steps Government have date will be on the transferer. This was taken to nullify such benami land transactions intended, among other things, to undo the effects of benami transfers of land that might have been done with a view to avoiding or evading the effects of the ceiling law. The ceiling laws of all the States accordingly provide for retrospective application of the law in a way that permits ignoring mala fide transfers.

Implementation of the report of committee on Urban Wastes

721. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state the steps taken by implement Government to recommendations of the Committee on Urban Wastes which was set up under the Chairmanship of Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI H. K. L. BHAGAT): A High Powered Implementation Committee has been set up under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Works and Housing to examine effectively implement recommendations of the Committee on Urban Wastes.

On the basis of the interim recommendations made by the Committee on Urban Wastes a new Scheme called the "Central Scheme of Solid Wastes Disposal" has been sanctioned. The Scheme envisages (i) the setting up of mechanical composting plants in cities having population of 3 lakhs and above and (ii) strengthening the infrastructure to feed these plants and to improve the cleanliness of the cities. Under the Scheme, Projects for 11 cities namely, Ahmedabad, Madras, Calcutta, Baroda, Bangalore, Lucknow. Kanpur, Varanasi, Allahabad, Jaipur and Bombay have been sanctioned. Projects for five more cities namely, Amrit-sar, Ludhjana, Jullundur, Jodhpur and Delhi have also been approved for sanction.

दिल्ली में शराब की दकानें 722. श्री श्रोम प्रकाश त्यागी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंदी 26 मई, 1976 को राज्य सभा में घतारांकित प्रका 487 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे

Written Answers

- (क) क्या दिल्ली में देसी और विदेशी शराब की दकानें खोलने के संबन्ध में कोई निर्णय लिया गय। है :
- (ख) यदि हां, तो इस वर्ष ग्रब तक ऐसी कितनी दुकाने खोली गई ;ग्रीर
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी दुकानें खोली गई और इस खबधि में दिल्ली में देसी और विदेशी शराब की कुल कितनी खपत

†[Liquor shops in Delhi

722. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 487 given in the Rajya Sabha on the 26th May, 1976 and state:

(a) whether any decision has been taken to open country made and foreign liquor shops in Delhi;

to Questions

- (b) if so, the number of shops opened so far during this year; and
- (c) what is the number of such shops opened during the last three years and what is the total consumption of countrymade and foreign liquor in Delhi during that period ?]

शिक्षा ग्रीर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री घरविन्द नेतम) : (क) ग्रीर (ख) वर्ष 1976-77 के दौरान देशी भराव के लिए 10 दकानों की, भारत में निर्मित विदेशी गराब (थोक) के लिए 23 दकानों को, भारत में निर्मित विदेशी णराब (खुदरा) के लिए 34 दुकानों को तथा केवल बीयर की खुदरा विकय के लिए 4 दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए।

(ग) एक विवरण, जिसमें यह जानकारी दी गई है, संलग्न है।

दिल्ली में 1973-74, 1974-75 तथा 1975-76 में शराब की दुकानों की संख्या तथा देशी और विदेशी शराब की खपत

भारत में निर्मित विदेशी भराव की दुकानों की संख्या	भारत में निर्मित विदेशी षराब की खपत (किलोलिटर)	बीयर की खपत (किलो- लिटर)	देशी शराब की दुकानों की संख्या	देशी शराब की खपत
श्रोक (एल-1)-27 खुदरा (एल-2)-28	1,775	3,076	7	3,954
−यबोपरि−	2,063	2,807	7	4,947
-यथोपरि-	2,254	2,216	7	6,053
	बिदेशी भराव की दुकानों की संख्या बोक (एल-1)-27 खुदरा (एल-2)-28 -यबोपर-	बिदेशी भराब की निर्मित विदेशी सुकानों भी संख्या शराब की खपत (किलोलिटर) बोक (एल-1)-27 1,775 खुदरा (एल-2)-28 -यशोपर- 2,063	बिदेशी भराब की निर्मित विदेशी स्वपत दुकानों भी संख्या भराब की (फिलो- खपत लिटर) (किलो/लिटर) बोक (एल-1)-27 1,775 3,076 खुदरा (एल-2)-28 -यथोपरि- 2,063 2,807	बिदेशी भराब की निर्मित विदेशी खपत की दुकानों दुकानों भी संख्या खराब की (किलो- की संख्या खपत किलो- किर संख्या किर संख्या किलो- किर संख्या किर

t[THE DEPUTY MINISTER IN THE | for Indian Made Foreign Liquor (wholesale), EDUCATION MINISTRY OF AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DE-PARTMENT OF CULTURE ARVIND NETAM): (a) and (b) During the year 1976-77 licences were issued for 10 shops for Country Liquor, 23 shops

34 shops for Indian Made Foreign Liquor (Retail) and 5 shops for retail sale of beer exclusively.

(c) A statement furnishing the information is enclosed.

t[] English translation.

.

Statement

The number of Liquor shops and the consumption of country made and foreign made Liquor in Delhi during 1973-74 to 1975-76

Year	٠. ٨	No. of Indian Made Foreign Liquor Shops	tion of Indian Made	Consumption of Beer (Kilo-litres)	No. of Country Liquor Shops	Consump tion of Country Liquor (Kilo- litres)
1973-74	•	. Wholesale (L-1)-27 Retail (L-2)-28	1,775	3,076	7	3,954
1974-75		, Do. (get	2,063	2,807	7	4,947
1975-76		. Do.	2,254	2,216	7	6,053]

गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये श्राक्षार्य बिनोबा भावे द्वारा श्रनशन

723. श्री म्रोम प्रकाश त्यागी : नया कृषि श्रीर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि आचार्य दिनोबा भावें ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगार्ये अन्यया वे निकट भविष्य में ग्रामरण अनवन कर सकते हैं; और
- (बा) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

f[Fast untodeatb by Acharya Vinoba Bhave for banning Cow Slaughter

723. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that Acharya Vinoba Bhave has urged Government to ban cow slaughter or else he may go on fast upto death in the near future; and
- (b) if so, what is Government's reaction in the matter?]

कृषि और सिंचाई मंत्रो (श्री जगजीवन राम): (क) ग्रीर (ख) सरकार का ध्यान इस समाचार की ग्रीर दिलाया गया है कि ग्राचार्य विनोबा भावे ने 11 सितम्बर, 1976 तक सारे भारत में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है, जिसके न किए जाने पर वे ग्रानिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल शुरू कर देंगे।

मवेशियों के बध निषेध, संरक्षण तथा सुधार का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्ट 15 के अन्तर्गत राज्यों का विषय है। अतः राज्य सरकारों गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत कानूनी उपाय कर सकती हैं।

t[THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI JAG-JIVAN RAM): (a) and (b) Government's attention has been drawn to reports that Acharya Vinoba Bhave has rlemanded a total ban on cow slaughter throughout India by the 11th September, 197S failing which he would enter on an indefinite fast.

The subject of prohibition, protection and improvement of stock is a State subject under Entry 15 of List II in the Seventh Schedule of the Consfitutioc. Legislative measures can, therefore, be taken by the State Governments under the existing provisions to ban cow slaughter.]

t[] English translation